शास्त्री - Ist   16/10/20

शास्त्री - Ist Part

## उत्पादन के दो मौलिक साधन

(Land and Labour are two original Factors of Production)

Date

हम जानते है कि उत्पादन के पाँच साधन है - भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवस्था एवं साहस। वास्तव में उत्पादन का काम इन पाँच साधनों के सहयोग से होता है इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

लेकिन Prof. Hecks के अनुसार उत्पादन के दो ही मुख्य मूल साधन हैं - (i) श्रम, (ii) पूंजी। उत्पादन का कार्य इन्हीं दोनों के सम्मिलित सहयोग से होता है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक स्थिति में मनुष्य भूमि एवं श्रम के सहयोग से ही अपना जीवन व्यतीत करता था, भूख लगने पर वह वनों से फल-फूल तोड़कर खा लेता था, तथा प्यास लगने पर जलाशय से जल पीकर अपना काम चला लेता था, इन लोगों के अनुसार भूमि और श्रम के बिना उत्पादन का कार्य नहीं हो सकता अतः वे उत्पादन के अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवार्य साधन हैं। इस मत के अर्थशास्त्री पूंजी को उत्पादन का मौलिक साधन नहीं मानते हैं। पूंजी पिछले श्रम का परिणाम है। यह भूमि और श्रम के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है अतएव इसे उत्पादन का मौलिक साधन नहीं कहा जा सकता। किन्तु वास्तव में आज के विशालकाय उद्योगों के युग में पूंजी का इतना महत्व हो गया है कि इसे उत्पादन का एक पृथक एवं महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जहाँ तक श्रम का सवाल है यह उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम के अन्तर्गत मनुष्य के वे सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न आते हैं, जो किसी आर्थिक उद्देश्य से किये जाते हैं। मनुष्य द्वारा ही भूमि को उत्पादन के कार्य में जोड़ा जाता है। इसलिए श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन (Active Factor) है और भूमि उत्पादन का निष्क्रिय (Passive) साधन है। प्रो० Hecks ने भूमि को उत्पादन का पृथक (अलग) साधन नहीं मानकर इसकी गणना पूंजी के अन्तर्गत की है। भूमि को इन्होंने पूंजी का अंश स्वीकार किया है कि भूमि को पूंजी के उपयोग द्वारा ही उत्पादन के योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार इन्होंने व्यवस्था को भी एक विशिष्ट प्रकार का श्रम बतलाते हुए इसे उत्पादन का एक स्वतंत्र साधन नहीं मानकर इसकी गणना श्रम के अन्तर्गत की है। किन्तु वास्तव में भूमि को पूंजी का एक अंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि भूमि प्रकृति-प्रदत्त (free gifts of nature) है पर प्रायः मनुष्य होते हैं, किन्तु पूंजी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती है। अतएव, भूमि को पृथक साधन मानना अति आवश्यक है।

16/10/20 [illegible]

R.N.S. College Sukhdena.

आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व — उपशास्त्री - IInd

(Role of Money in Economic life) Date 16/10/20

मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में मुद्रा हमारी आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है। मुद्रा ने केवल वर्तमान समय में बड़े पैमाने का उत्पादन को ही सम्भव बनाया है वरन् इसने आधुनिक रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाली विभिन्न वस्तुओं के विनिमय एवं वितरण की सुविधा भी प्रदान की है। मुद्रा समाज में भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर व्यक्ति की आय के वितरण को इस प्रकार से सम्भव बनाती है जिससे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। मार्शल के अनुसार आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। इसलिए यह कहा गया है कि "मुद्रा वस्तुतः पूंजीवाद का प्रतीक है। (Money is the Symbol of Capitalism.) हमारी आर्थिक क्रियाएं मुद्रा की प्राप्ति एवं व्यय से ही सम्बन्धित हैं। मुद्रा के सम्बन्ध में पीगू का यह कथन बिल्कुल ही सत्य है कि "आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किये हुए है" In the modern world industry is closely enfolded in the garment of money.) वस्तुतः मुद्रा आधुनिक आर्थिक जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। मुद्रा की सहायता से ही उपभोक्तागण कम मूल्य पर एवं सस्ता सामान खरीदते हैं तथा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों एवं प्रबन्धकों आदि की सेवाएं प्रदान करती है। किन्तु मुद्रा का महत्व व्यापार तथा व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहता है वरन् कुशल गृह-पत्नियों को भी अपने पारिवारिक बजट बनाने में मुद्रा से सहायता मिलती है। इसके द्वारा एक निश्चित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना सम्भव हो गया है। मुद्रा समाज के सदस्यों को उपलब्ध सीमित साधनों के मितव्ययितापूर्ण प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इस भौतिक युग में हमारी सफलता एवं असफलता भी मुद्रा के रूप में ही मापी जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक दिशा में आधुनिक जीवन मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होता है। मुद्रा के इसी महत्व को ध्यान में रखकर ही ट्रेसकोट (Trascot) ने कहा है कि "यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य ही है।" (If money is not the heart of our economic system it can certainly be considered its bloodstream.)

16/10/20

Bhawan

R.N.J. College Sukhsena

भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण Nationalization of Banks in India

शास्त्री - II 16/10/20 ~~शास्त्री~~ - IInd Part

वर्तमान समय में बैंक समाज के संपूर्ण आर्थिक विकास की स्थायी आधारशिला है। वास्तव में बैंक समाज की अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन में बैंकों का भारी योगदान है तथा देश का आर्थिक विकास बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय को निजी व्यक्तियों के हाथों में न छोड़कर उनका राष्ट्रीयकरण करना उचित समझा। इसी क्रम में 19 July 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके पश्चात 9 अगस्त 1969 को इसी आशय का एक कानून संसद द्वारा पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत भारत के प्रमुख 14 व्यापारिक बैंकों को सरकार ने अपने स्वामित्व एवं प्रबंधन में ले लिया। इन बैंकों के अंशधारियों को इसके बदले में मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी। जिन चौदह (14) बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे निम्नलिखित हैं :- (1) Bank of India (2) बैंक ऑफ बड़ौदा (3) Central Bank of India (4) Punjab National Bank (5) Canara Bank (6) Indian Bank (7) Allahabad Bank (8) Syndicate Bank (9) Dena Bank (10) United Bank of India (11) Indian Overseas Bank (12) Bank of Maharashtra (13) United Commercial Bank (14) Union Bank of India. पुनः दूसरी बार 15 April 1980 को भारत सरकार ने अन्य छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। इन छह बैंकों के नाम निम्नांकित हैं :- (1) Andhra Bank (2) Corporation Bank (3) New Bank of India (4) Oriental Bank of Commerce (5) Punjab and Sindh Bank and (6) Vijaya Bank. इस तरह स्टेट बैंक आफ इंडिया को छोड़कर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बढ़कर 20 हो गयी। अब कुल मिलाकर 91% बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हो चुका। इस पर निजी क्षेत्र का हिस्सा घटकर केवल 4.5 प्रतिशत रह गया है, तथा शेष 4.5 प्रतिशत विदेशी बैंक हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :- (1) बैंकिंग व्यवस्था में जन विश्वास जागृत करना :- बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में जन विश्वास जागृत करना। (2) राष्ट्रीय बचत में वृद्धि :- प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जनता की बचतों को एकत्रित करके उसे उत्पादन में लगानेवाली संस्थाओं को राजकीय स्वामित्व के अन्तर्गत लाने की ओर पहला कदम है। बचतों को जमाओं के रूप में संग्रहित करके राष्ट्रीय बचत में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। (3) बैंकिंग सुविधा में विस्तार :- राष्ट्रीयकरण का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना था ताकि सर्वसाधारण में बैंकिंग आदत का विकास किया जा सके। (4) बैंकिंग विकास के लिए वित्त :- बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी रहा है कि आर्थिक विकास की दिशा में वित्तीय अभाव को दूर किया जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य बैंक साख एवं साधनों पर उचित एवं प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि उसका अधिकतम उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके।

R.U.S. College Sunhsena.

16/10/20 [signature]